बीएसई 888.68 77,654.60 | एनएसई 264.85 24,250.20 | **कारोबार** | डॉलर ₹0.06 ₹95.76 | सोना /10 ग्राम ₹1,46,200 | चांदी /1 किग्रा ₹2,22,700 सराफा बाजार की दरों में

न्यूज़ डायरी

अदाणी इंटरप्राइजेज को 1,160 करोड़ का घाटा

नई दिल्ली। अदानी समूह की प्रमुख कंपनी अदानी इंटरप्राइजेज की वित्त वर्ष 2026-27 की जून तिमाही में 1,160 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ। पिछले वर्ष की समान अवधि में कंपनी 885 करोड़ लाभ में थी। आय 50 फीसदी बढ़कर 33,546 करोड़ रही। उधर, पतंजलि फूड्स का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर करीब 40 फीसदी बढ़कर 1,559.45 करोड़ रुपये हो गया। एजेंसी

सेबी ने रद्द किया 10 विरलेषकों का पंजीकरण

नई दिल्ली। सेबी ने नवोन्मेषण शुल्क जमा नहीं करने पर 10 शोध विश्लेषकों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इनमें हिमेवाश रामन मर्चेंट, प्रवीण पंचियिल, इनमनर्ट सिस्टमें सर्विसेज, एफएसएस फिनकॉर्प सर्विस, दिव्य कलाट रंडाइस और फ्रूल्स मोहर आदि शामिल हैं। इन्होंने जुलाई 2020 से दिसंबर 2025 के बीच शुल्क जमा नहीं किया था। एजेंसी

मणिपाल हेल्थ आईपीओ पहले दिन 15% भरा

नई दिल्ली। अस्पताल मुंबला चलाने वाली कंपनी मणिपाल हेल्थ के 9,275 करोड़ रुपये का आईपीओ पहले दिन 15 फीसदी सब्सक्राइब हुआ। इसमें खुदरा निवेशकों की भागीदारी करीब 25 फीसदी रही। यह इसमें 31 जुलाई तक खुला रहेगा। शेयरों की कीमत 560 से 590 रुपये तय की गई है। 5 अगस्त को शेयर बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होंगे। कंपनी पहले ही बड़े निवेशकों से 4,167 करोड़ रुपये जुटा चुकी है। एजेंसी

भारतीय कंपनियों की कमाई 9% तक बढ़ेगी

नई दिल्ली। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय कंपनियों की आमदनी में करीब 9 फीसदी वृद्धि का अनुमान लगाया है। पिछले वित्त वर्ष में यह सिर्फ 5 फीसदी थी। इंडिया कॉरपोरेट क्रेडिट ट्रेंड्स जुलाई 2026 रिपोर्ट में फिच ने कहा, कंपनियों की कर्ज की क्षमता स्थिर रहने की उम्मीद है। हालांकि, अमेरिका-ईरान तनाव फिर बढ़ने से कमाई पर असर दिख सकता है। एजेंसी

रूस ने टेलीग्राम प्रमुख को घोषित किया आतंकी

मॉस्को। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव पर आतंकी गतिविधियों में मदद करने का आरोप लगाया है। एजेंसी ने दुरोव को अंतरराष्ट्रीय वांछित आतंकियों की सूची में शामिल करने की बात कही है। एफएसबी ने कहा कि यूक्रेनी जासूस टेलीग्राम का इस्तेमाल रूस में हमले कराने के लिए कर रहे थे।

FORM NO.
[See Regulation 33(2)]
OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR
2nd & 3rd Floor, Sanchar Vikas Bhavan (BSNL Building), Near Head Post Office Residency Road, Jabalpur -482001, MP.
NOTICE FOR SETTLING A SALE PROCLAMATION UNDER RULE 53 OF THE SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993.
RC/205/2025 14.07.2026
STATE BANK OF INDIA
Versus
AMAN SINGH
To,
(CD1) AMAN SINGH
1322, PRIYADARSHINI SOCIETY, KAILASH NAGAR, BHILAI (C.G.)-491001 AND FLAT NO 502, HARSHIT DIAMOND TOWER, HEERAPUR, WARD NO 13, RAIPUR(C.G.)-492099
Also At: FLAT NO 502, HARSHIT DIAMOND TOWER, HEERAPUR, WARD 13, RAIPUR(C.G.)
Whereas you the AMAN SINGH was ordered by the Presiding Officer of DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JABALPUR who had issued the Recovery Certificate dated 07/09/2025 in OA/1010/2021 to pay to the Applicant Bank(s)/Financial Institution(s)Name of applicant, the sum of Rs 2787573 (Rupees Twenty Seven Lakhs Eighty Seven Thousands Five Hundred Seventy Three Only) along with pendentelite and future interest @ 9.50 % w.e.f. 17/11/2021 till realization and costs of Rs 35000 (Rupees Thirty Thousands Only), and whereas the said has not been paid, the undersigned has ordered the sale of undermentioned immovable / immovable property.
2. You are hereby informed that the 21/08/2026 at 10.30 A.M. has been fixed for drawing up the proclamation of sale and settling the terms thereof. You are requested to bring to the notice of the undersigned any encumbrances, charges, claims or liabilities attached to the said properties or any portion thereof.
Specification of property
Residential Property Flat No.-502 at Khasra No.-641/6-8, Fifth Floor, Harshit Diamond Tower, Condominium Hingour alias Janvy Shahid Bhagat Singh Ward No. -13, P.H. No.-105 (As per valuation report PH No. 103/35), Rd Circle Raipur-1, District-Raipur(C.G.), area 1020 sq.ft Property in the name of Shri Aman Singh S/o Rakesh Singh.
Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: 14/07/2026.
Sd/-
Recovery Officer
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur
SEAL

2030 तक 2 करोड़ होगी गिग कर्मियों की संख्या, महिलाएं सिर्फ 1%

रेडसीर रिपोर्ट में खुलासा : गिग सेक्टर बना रोजगार का बड़ा माध्यम, मिलेंगी 70% नौकरियां

नई दिल्ली। देश में गिग इंटरनेट कामगारों की संख्या वर्ष 2030 तक 2.1 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, तेजी से बढ़ते इस रोजगार बाजार में महिलाओं की भागीदारी बेहद सीमित है। रेडसीर स्ट्रैटेजी की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 0.5% थी, जो 2025 में बढ़कर करीब एक फीसदी हो गई है। इसके मुकाबले भारत में कुल महिला श्रम भागीदारी दर करीब 28 फीसदी है।

अधिकांश महिलाएं ब्यूटी और वेलनेस सेवाओं से जुड़ी हैं। इसमें उनकी हिस्सेदारी 35 से 45 फीसदी के बीच है, जबकि फूड डिलीवरी में भागीदारी एक फीसदी से भी कम बनी हुई है।

नौकरियों में अहम भूमिका

वर्तमान में भारत में करीब 60 लाख मासिक सक्रिय गिग इंटरनेट वर्कर्स हैं। वर्ष 2030 तक यह संख्या बढ़कर 1.7 करोड़ से 2.1 करोड़ के बीच पहुंच सकती है।

इस दशक के अंत तक कुल नौकरियों का 70 फीसदी हिस्सा गिग सेक्टर पूरा कर सकता है।

2.5 गुना अधिक कमाई

फुल-टाइम गिग वर्कर्स की सामान्य नौकरियों की तुलना में 2.5 गुना तक अधिक है।

- औसत प्रति घंटा कमाई 138 रुपये रही, जबकि अन्य कर्मचारियों की औसत कमाई 54 रुपये प्रति घंटा है।

घरेलू सेवाएं सबसे आगे

मासिक आय के लिहाज से घरेलू सेवाएं सबसे अग्रणी रहीं। इस क्षेत्र में फुल-टाइम कर्मियों की शुद्ध आय 80,000 रुपये तक रही। ड्राइवरों की आय 39,000 रुपये और डिलीवरी वर्कर्स की 22,000 से 23,000 रुपये के बीच रही।

54% लोगों को पहली बार मिला रोजगार

54 फीसदी लोग दिन पहेड़ाओं से जुड़ने से पहले कोई काम नहीं कर रहे थे। यह सेक्टर पहली बार नौकरी करने वालों और बेरोजगारों के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम बन रहा है।

ड्राइवरों की संख्या 1.4 करोड़ पहुंचने का अनुमान. वर्ष 2030 तक राइट-हेलिंग बिजनेस (एप से कैब बुकिंग) में 1.2 से 1.4 करोड़ गिग वर्कर्स होने का अनुमान है। डिलीवरी सेक्टर में 50 से 70 लाख और होम सर्विसेज में करीब 2 से 3 लाख कामगारों के होने की संभावना जताई गई है।

एलआईसी ने निर्मला को दिया 12,207.25 करोड़ का डिविडेंड चेक

मुंबई। प्र. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने अपने गठन के 70 साल पूरे कर लिए हैं और उसका एसेट बेस 59.03 लाख करोड़ रु हो गया है। भारतीय जीवन बीमा मार्केट में यह लगातार लीडर बना हुआ है। एलआईसी के सीईओ और एमडी आर दोरैस्वामी ने वित्त एटनाकल, एमडी आर चंदर और मंत्रियों ऑफिसर एपएस रायथ भी मौजूद थे।

डिविडेंड चेक प्रदान किया। इस डिविडेंड को एलआईसी की 27 जुलाई को आयोजित एजीएम में शेयरहोल्डर ने मंजूरी दी है। इस अवसर पर वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवाओं के विभाग के सेक्रेटरी संजय लेठिया के साथ साथ एलआईसी के एमडी रत्नाकर पटनायक, एमडी आर चंदर और मंत्रियों ऑफिसर एपएस रायथ भी मौजूद थे।

गोल्ड लोन लेने वालों की मुश्किलें बढ़ेंगी, हर महीने देनी होगी किस्त

एनबीएफसी कंपनियां एकमुश्त भुगतान की जगह ईएमआई से करेंगी वसूली

संवाद न्यूज एजेंसी।नई दिल्ली।

अगर आप अपनी किसी आपातकालीन जरूरत, बिजनेस या निजी काम के लिए सोने के गहने गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं, तो जल्द ही आपको बड़ा झटका लग सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा के अनुसार, देश का गोल्ड लोन बाजार आने वाले दिनों में एक बड़े संरचनात्मक बदलाव से गुजरने जा रहा है। इस अहम बदलाव से जहां एक तरफ गोल्ड लोन लेना और उसे चुकाने का तरीका बदल जाएगा, वहीं दूसरी तरफ गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) यानी फंसे हुए कर्ज में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब तक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से गोल्ड लोन लेने वाले करीब 90 फीसदी ग्राहक एकमुश्त भुगतान (बुलेट पेमेंट) का विकल्प का इस्तेमाल करते थे। इसमें ग्राहक को लोन की अवधि (जैसे 6 महीने या 1 साल) के दौरान हर महीने किस्त नहीं देनी होती थी। लोन खत्म होने पर मूलधन और ब्याज की पूरी रकम एक साथ चुकानी होती थी। लेकिन अब इसे नियमित मासिक किस्त वाले लोन में बदलने से निकट भविष्य में बकाया बढ़ सकता है, क्योंकि लेनदार बुलेट पेमेंट के मुकाबले नई प्रणाली के हिसाब से बढ़ा को झेलने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं।

बाजार पर कितना असर?

इक्रा के मुताबिक, बैंकों और एनबीएफसी का कुल गोल्ड लोन वित्त वर्ष 2026-27 से 2027-28 के दौरान 30 फीसदी से अधिक की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ेगा। यह मार्च 2026 के लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2028 तक 30 लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगा। अगले वित्त वर्ष तक एनबीएफसी की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 23 फीसदी होने का अनुमान है।

एनपीए बढ़ने का जोखिम गहराया

इक्रा का अनुमान है कि बुलेट पेमेंट से निर्धारित ईएमआई प्रणाली में जाने के दौरान निकट भविष्य में गोल्ड लोन से जुड़ा एनपीए बढ़ सकता है। आरबीआई के मुताबिक, स्वर्ण आभूषण के बदले लिया गया बकाया कर्ज, 31 मई, 2026 तक बढ़कर 5.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है। कैलेंडर वर्ष 2026 में कुल बकाया कर्ज में 105 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा?

- बुलेट भुगतान में लोन अवधि के दौरान मूलधन कम नहीं होता। यदि वित्तीय या परंतु बाजार में सोने के भाव अचानक गिरते हैं, तो कैश या एक्सपोजरों में अतिरिक्त सोना गिरवी रखने या लोन का कुछ हिस्सा तुरंत चुकाने को कह सकते हैं। नए मॉडल में चूंकि हर महीने कुछ न कुछ भुगतान होता रहेगा, इसलिए सोने के भाव घटने-बढ़ने पर जोखिम नियंत्रित रहेगा।

नियम बदलने से छोटे कर्जदारों और आम ग्राहकों को हर महीने बजट व्यवस्थित करने में परेशानी आ सकती है। पहले पैसा साल के अंत में देना होता था, लेकिन अब हर महीने देना होगा। अगर कोई ग्राहक लोन नहीं चुका पाता है, तो केंद्रीयमा गिरवी रखे गए सोने की नीलामी करके अपना पैसा वसूल करती हैं।

टेक शेयरों के दम पर सेंसेक्स 889 अंक उछला निफ्टी आईटी में भी तेजी

नई दिल्ली। कच्चे तेल में तेजी के बावजूद भारतीय शेयर बाजारों ने बुधवार को कई वैश्विक सूचकांकों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। एआई का जादू फीका पड़ने से पार्पलिक आईटी शेयरों को लेकर निवेशकों के बड़े भरोसे से बाजार को मजबूती मिली। आईटी सेक्टरों में चौतरफा खरीदारी और विदेशी संस्थागत निवेशकों की वापसी के दम पर बीएसई सेंसेक्स 888.68 अंक यानी 1.16 फीसदी चढ़कर 77,654.60 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 999.57 अंक चढ़कर 77,765.49 अंक तक पहुंच गया था। निफ्टी 264.85 अंक यानी 1.10 फीसदी की बढ़त के साथ 24,250.20 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी आईटी सूचकांक में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी रही। यह 2.32 फीसदी चढ़कर 31,123.10 के स्तर पर बंद हुआ।

आईटी शेयरों की बढ़ी चमक

कंपनी	तेजी
इंफोसिस	4.32%
केपीआईटी टेक	5.98%
टीसीएस	1.75%
एचसीएल	1.70%
कोफोर्ज	1.25%
विप्रो	1.20%

- एक्सिस डायरेक्ट के वरिष्ठ रिसर्च हेड राजेश पालविया के अनुसार, जब तक निफ्टी 23,880 के सपोर्ट जोन से ऊपर बना रहता है, तब तक बाजार का रुझान सकारात्मक बना रहेगा। 24,100–24,150 के प्रतिरोध के ऊपर निर्णायक बढ़त निफ्टी को 24,400 की ओर ले जा सकती है। बोनस डेक्स

भारत पर 100% टैरिफ का विधेयक सीनेट से पास, कांग्रेस की मंजूरी बाकी

रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सख्ती, विधेयक को 86-12 से समर्थन

वाशिंगटन। अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार को रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़े एक अहम विधेयक को मंजूरी दे दी। विधेयक में रूस से हैरन खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी विधेयक का समर्थन किया है। भारत उन पांच बड़े देशों में शामिल है, जिन पर इस टैरिफ का सीधा असर पड़ेगा।

यह डिटरेंस (रिपोजिशन-डेमोक्रेट) विधेयक इसके प्रायोज्य समर्थक रहे दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम की पहल पर तैयार किया गया था। मंगलवार को सीनेट में इसके पहले प्रक्रियागत प्रस्ताव के पक्ष में 86 और विरोध में 12 मत पड़े। अब विधेयक को प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या कांग्रेस) में भेजा जाएगा। वहां मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह कानून बन जाएगा।

विधेयक में ईरान पर भी नए प्रतिबंध का प्रावधान है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था, आतंकवाद को समर्थन देने और परमाणु कार्यक्रम चलाने की क्षमता सीमित की जा सके।

रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों वाले प्रमुख देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी विधेयक का समर्थन किया है। भारत उन पांच बड़े देशों में शामिल है, जिन पर इस टैरिफ का सीधा असर पड़ेगा।

विधेयक में ईरान पर भी नए प्रतिबंध का प्रावधान है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था, आतंकवाद को समर्थन देने और परमाणु कार्यक्रम चलाने की क्षमता सीमित की जा सके।

रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों वाले प्रमुख देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी विधेयक का समर्थन किया है। भारत उन पांच बड़े देशों में शामिल है, जिन पर इस टैरिफ का सीधा असर पड़ेगा।

यह डिटरेंस (रिपोजिशन-डेमोक्रेट) विधेयक इसके प्रायोज्य समर्थक रहे दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम की पहल पर तैयार किया गया था। मंगलवार को सीनेट में इसके पहले प्रक्रियागत प्रस्ताव के पक्ष में 86 और विरोध में 12 मत पड़े। अब विधेयक को प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या कांग्रेस) में भेजा जाएगा। वहां मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह कानून बन जाए